

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 34 वर्ष 2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधशासी अभयन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, डोईवाला द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

अधशासी अभयन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, डोईवाला के माह 12/2015 से 07/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर.एन.यादव, श्री डी.के. मट्टू एवं श्री राजेश डोभाल, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 12/08/2017 से 23/08/2017 तक श्री नीरज चुंगू वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मक: इस इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा।

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 12/2015 से 07/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

(i) इकाई के क्रयकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: अनुरक्षण का कार्य जनपद देहरादून के अन्तर्गत विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग। (NH-72 (New-07), NH-58, NH-707A, NH-723

(ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आ धक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2015-16	-	-	3435266.00	3435266.00				
2016-17	-	-	29651802.00	29414729.00				237073.00

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निध एवं व्यय ववरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	व्यय अधक्य (+)	बचत (-)
शून्य						

- (iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड शासन द्वारा कया जाता है। गैर-स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

स चव उत्तराखंड शासन, लोक निर्माण वभाग, उत्तराखण्ड शासन

प्रमुख अ भयन्ता एवं वभागध्यक्ष उत्तराखण्ड, लोक निर्माण वभाग

मुख्य अ भयन्ता, रा.मा. लो.नि. व.

अधीक्षण अ भयन्ता, रा.मा., लो.नि. व.

अ धशासी अ भयन्ता, रा.मा., लो.नि. व., उत्तराखण्ड

- (iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण वभाग, डोईवाला को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अ धशासी अ भयन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण वभाग, डोईवाला की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017 एवं 06/2017 को वस्तुतः जाँच हेतु चयनित कया गया। Construction of 4 lane POB in Km 165 on NH 72 at Mohkanpur Railway crossing at Dehradun का वस्तुतः वश्लेषण कया गया।
- (v) लेखापरीक्षा भारत के संवधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

2. अधीक्षण अ भयन्ता द्वारा वगत लेखापरीक्षा से अब तक की अव ध में दिनांक से का निरीक्षण कया गया।
3. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 03/17 तथा तक की गई।

4. फार्म 51: माह 07/17 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैं:-

भाग प्रथम - (-) 3799775/-

भाग द्वितीय - ₹ 1631531/-

5. खण्ड के उच्चतम लेखों के अवशेष माह 07/17 के अन्त में

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रम - ₹ शून्य

(ख) सामग्री क्रय - शून्य

(ग) नगद परिशोधन - शून्य

(घ) निक्षेप- ₹ 18,13,26,851/-

(ङ) भण्डार- ₹ 17,14,601/-

भाग 2 ब

प्रस्तर 1: अपूर्ण कार्य के निष्पादन के उपरांत भी वभागीय शथलता के कारण क्षतिपूर्ति ठेकेदार से वसूली कए बिना ही बैंक गारंटी ` 59.41 लाख की ठेकेदार को अवमुक्त होना। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (नया नंबर 07) के कमी० 156 से 161 (आई एस बी टी से अजबपुर रेलवे क्रा संग) मे मार्ग के दो लेन से चार लेन चोड़ीकरण कार्य के लए प्रशासकीय एवं वतीय स्वीकृति भारत सरकार द्वारा लागत `2042.44 लाख (जॉब संख्या एन० एच० 72 नया 07-UR-2011-12-279)की प्राप्त हुई थी। कार्य के निष्पादन हेतु मेसर्स अमृत इवल्लेर्स प्राइवेट ल मटेड के साथ अधीक्षण अभ्यन्ता 10 वा व्रत द्वारा अनुबन्ध संख्या 34/SE-एनएच/12-13 दिनांक 04/09/2012 लागत `1188.04 लाख (जिसके अंतर्गत पुल,गु लयो के निर्माण पर `464.64 लाख, नाली मी डयन के निर्माण पर `124.58 लाख व सड़क निर्माण पर `598.82लाख का कार्य कया जाना था) का अनुबन्ध गठित कया। अनुबन्ध के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथ 04/09/2012 व समाप्ति की तिथ 03/03/2014 (18 माह) थी तथा अनुबन्ध के अनुसार कार्य पर 3 माइल स्टोन प्रथम 4 ½ माह मे 25%,9 माह मे 50 % व 18 माह मे 100 % निर्धारित कए गए थे अनुबन्ध के बिन्दु संख्या 40-व बिन्दु 60-के अनुसार ठेकेदार के कार्य अपूर्ण रखने पर अवशेष कार्य पर 20% प्रतिशत का अर्थदण्ड लगाया जाना था।

अधशासी अभ्यन्ता,राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण वभाग, डोईवाला के अभलेखो की जांच मे पाया गया क अपूर्ण कार्य के निष्पादन मे कुल `235.63 लाख (पुल,गु लयो के निर्माण पर `23.56 लाख व सड़क निर्माण पर `212.07 लाख) का व्यय कया गया तथा अनुबन्ध को अधीक्षण अभ्यन्ता द्वारा कार्य की काफी धीमी प्रगति होने के कारण 03/5/2014 को निरस्त कया तथा अवशेष कार्य की धनराश पर अर्थदण्ड `1.89 करोड़ (प्रतिशत 20) लगाया गया जो क कुछ हद तक खण्ड के पास ठेकेदार की जमानत धनराश बैंक गारंटी `59.41 लाख जिसकी वैधता 30/8/2012 से 28/05/2014 तक थी से वसूली समायोजन कया जा सकता था।जो क खण्ड द्वारा नहीं कया गया व ठेकेदार को बैंक गारंटी निकालने का मोका दिया गया। अतः `1.89 करोड़ लाख क क्षतिपूर्ति ठेकेदार से वसूली नहीं गयी है और न ही उक्त वसूली हेतु कार्यालय द्वारा जनवरी 2015 के उपरान्त कोई कारवाही सुनिश्चिती की है। अतः खण्ड द्वारा `1.89 करोड़ क क्षतिपूर्ति धनराश ऋणात्मक मद मे वसूले जाने हेतु रखी गयी है। इस के अतिरिक्त कार्य के सम्पादन मे प्रस्तुत अभलेखो के अनुसार निम्न तथ्य प्रकाश मे आये:

- अनुबन्ध मे 3 सेतुओ का निर्माण सम्मिलत था ले कन ठेकेदार के पास सेतु निर्माण का अनुभव नहीं था तथा कार्य स्थल पर अनुभवी अभ्यन्ता के अभाव के कारण

9.11.2012 पर मार्ग में existing सेतु की वग वाल को भी गरा दिया था जिस से उक्त मार्ग पर 2 दिन तक यातायात बाधत रहा था।

- एसबीडी के क्लॉज संख्या 27 के अनुसार ठेकेदार द्वारा वर्क प्रोग्राम खण्ड को उपलब्ध नहीं कराया था।
- एसबीडी के क्लॉज संख्या 13 के अनुसार ठेकेदार द्वारा कार्य पर बीमा भी नहीं कराया था।
- ठेकेदार को black लस्ट कये जाने हेतु मुख्य अभियन्ता, एन०एच०, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को भी नहीं लिखा गया था।
- ठेकेदार द्वारा योजित रिट पटिशन संख्या 1190(एसएस)/14 की सुनवाई कए जाने हेतु 18/11/2014 से खण्ड द्वारा कोई कारवाही नहीं की गयी थी।

उपरोक्त के सम्बंध में इंगत कए जाने पर अधशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग, डोईवाला ने अवगत कराया कि समस्त अभिलेख अधशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग, रूडकी से हस्तगत न होने के कारण इस सम्बंध में आख्या नहीं दे सकते जबकि इस सम्बंध में अधशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग, रूडकी द्वारा इस विषय में अवगत कराया कि समस्त अभिलेख अधशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग, डोईवाला को 19 जनवरी 2016 को हस्तगत कये गये हैं। आगे अधशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग, रूडकी द्वारा उपरोक्त तथ्यों को स्वीकार करते हुये यह भी अवगत कराया कि कार्य पर विभागीय स्तर से बैंक गारंटी ₹59.41 लाख अवमुक्त नहीं की गयी है। खंड का उत्तर तरकसंगत नहीं है क्योंकि इस सम्बंध में न तो अधशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग, डोईवाला और न ही अधशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग, रूडकी लेखा परीक्षा को बैंक गारंटी के खंड में उपलब्ध होने के साक्ष्य दे पाये और यह भी नहीं बता पाया कि ठेकेदार को कब व कैसे ₹59.41 लाख की बैंक गारंटी अवमुक्त हुई। इस के साथ साथ यह भी उल्लेखनीय है कि इस सम्बंध में दोनों खण्डों द्वारा कोई एफ० आइ० आर० नहीं किया गया था व कार्य को शीघ्र पूर्ण कए जाने हेतु ठेकेदार द्वारा योजित रिट पटिशन संख्या 1190एसएस पर माननीय उच्च न्यायालय से जल्दी सुनवाई कराये जाने हेतु 18/11/2014 से खण्डों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की है।

अतः विभागीय शकलता के कारण क्षतिपूर्ति ठेकेदार से वसूली कए बिना ही ₹59.41 लाख की बैंक गारंटी का ठेकेदार को अवमुक्त होना व एस० बी० डी० के क्लॉजों का अनुपालन न कये जाने से अपूर्ण कार्य निष्पादन पर कुल ₹235.63 लाख का व्यय उच्च अधिकारियों के सज्जन में लाया जाता है।

भाग 2 ब

प्रस्तर 2: मैसर्स रिलायंस जियो इन्फोकॉम ल मटिड से 'रोड कटिंग चार्जस' निर्धारण में ₹ 31.50 लाख की कम वसूली।

लोक निर्माण वभाग द्वारा बनाये गए मोटर मार्गों पर यदि कोई सरकारी / प्राईवेट संस्थान जल निगम / जैसे, दूरसंचार की कंपनी आदि के द्वारा मोटर मार्गों पर केबल पाइप लाइन / बिछाने के लिए मोटर मार्गों पर जो कटिंग का कार्य किया जाता है, उसके एवज में मार्गों पर कटिंग वाले स्थानों पर मरम्मत कराने हेतु 'रोड कटिंग चार्जस' के रूप में धनराश संबंधित वभाग द्वारा खण्ड को प्रदान की जाती है। इसकी गणना की दर प्रमुख अभ्यन्ता एवं वभागाध्यक्ष, उत्तराखंड लोक निर्माण वभाग, देहरादून द्वारा 16/5/2011 व 22/9/2016 के अनुसार निर्धारित की जानी है।

अधशासी अभ्यन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण वभाग, डोईवाला के लेखा अभिलेखों की जांच में पाया गया कि खण्ड द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 707 ए के कमी 61 से 93 (कुल 33 km) में 'रोड कटिंग चार्जस' (14-12-16) के 16500 sqm के लिये देय धनराश '127.96 लाख' के स्थान पर केवल 12000 sqm के लिये '96.46 लाख' पर ही निर्धारण कर मैसर्स रिलायंस जियो इन्फोकॉम ल मटिड को 'रोड कटिंग चार्जस' के रूप में '31.50 लाख की कम वसूली की गयी व लाभ पहुंचाया।

उपरोक्त के सम्बंध में इंगत किए जाने पर खण्ड ने ने तथ्यों को स्वीकार करते हुये अवगत कराया कि मैसर्स रिलायंस जियो इन्फोकॉम ल मटिड को 'रोड कटिंग चार्जस' के रूप में '31.50 लाख की कम वसूली करने हेतु पत्र निर्गत कर दिया गया है। खण्ड का उत्तर स्वतः ही लेखा परीक्षा बिन्दु की पुष्टि करता है।

अतः गलत निर्धारण/त्रुटि के कारण मैसर्स रिलायंस जियो इन्फोकॉम ल मटिड से 'रोड कटिंग चार्जस' के रूप में कुल ₹ 31.50 लाख की कम वसूली का प्रकरण उच्च अधिकारियों के सज्जन में लाया जाता है।

¹(12000sqm@700=₹84.00 + 4500 sqm@ 977=₹43.96 लाख)=₹127.96 लाख

²(7500@700=₹52.50 + 4500 sqm@ 977=₹43.96 लाख)

भाग 2 ब

प्रस्तर 3: अनुबन्ध के अनुसार कार्य पर धीमी प्रगति व एस० बी० डी० के क्लोजो का अनुपालन न कया जाना तथा ठेकेदार के भुगतान देयक से ` 2.39 लाख की रॉयलटी की कटौती न कया जाना तथा नियमों के विपरीत `122.91 लाख का भुगतान।

क) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 707 A के कमी० 165 से 233 कमी० में चोड़ीकरण / क्षतिग्रस्त कलवर्ट एवं नाली का पुनः निर्माण कार्य हेतु ` 561.76 लाख लागत की प्रशासकीय एवं वतीय स्वीकृति शासनादेश संख्या एनएच -1/2014/25/ 2016-यू० आर० -एनएच -1/दिनांक 28/11/2016 द्वारा प्राप्त हुई हैं। कार्य को मेसर्स के **construction** से अनुबन्ध संख्या 49/SE-एनएच-10/2017 दिनांक 16/3/2017 लागत `389.36 लाख के द्वारा कराया जा रहा है। कार्य प्रारम्भ 16/3/2017 व पूर्ण 15/09/2017 को कया जाना है।

अधशासी अभ्यन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग, डोईवालाके अभिलेखों की जांच में पाया गया कि कार्य के निष्पादन में आतिथ (अगस्त 2017) तक 60% के सापेक्ष केवल 11% की प्रगति थी जिसके लिए ठेकेदार द्वारा `45.09 लाख का देयक खण्ड को (30 जून 2017) प्रस्तुत किया है जिसका भुगतान आतिथ (अगस्त 2017) तक ठेकेदार को नहीं किया गया है जिस कारण से एसबीडी के क्लॉज 43 के अनुसार खंड को 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी देना पड़ सकता है। इस के अतिरिक्त कार्य के निष्पादन में:

- एस० बी० डी० के क्लोज संख्या 27 के अनुसार ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध में निर्धारित ile tone के अनुसार work programme खण्ड को उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही खण्ड द्वारा इसको प्राप्त किए जाने हेतु कोई प्रयास किया गया है।
- एस० बी० डी० के क्लोज संख्या 13 के अनुसार कार्य का बीमा नहीं कराया गया है।
- अनुबन्ध के अनुसार अब तक (प्रथम 2 माह में 20%, 4 माह में 60% व 6 माह में 100%) में 90% धनराश का कार्य पूर्ण किया जाना था परन्तु 5 माह से अधिक का समय होने के पश्चात भी अभी तक 11% कार्य भी नहीं किया गया है। इस के अतिरिक्त ठेकेदार से कार्य को समयान्तर्गत सम्पादित न किए जाने हेतु खण्ड द्वारा कोई पत्राचार अथवा अर्थदण्ड ठेकेदार के देयक से नहीं काटा है।

- ठेकेदार द्वारा ₹45.09 लाख का देयक खण्ड को प्रस्तुत किया गया है जिसमें रायल्टी की कटौती ₹2.39लाख नहीं की गयी है।

ख) राजमार्ग सं०-72 के किमी० 165 मोहकमपुर में ओवरब्रिज की स्वीकृति सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक एन०एच० 12037/34/2014 यू०आर०एन०एच० 2 दिनांक 20.06.2014 द्वारा वार्षिक योजना 2014-15 में अनुमोदित हुआ था। जिसके अनुपालन में इस कार्य का आगणन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली को माह जुलाई 2014 को प्रेषित किया गया था। मंत्रालय के पत्रांक RW-NH-12014/Uttarakhand (1)/2014-S&R (B) दिनांक 19.11.2014 द्वारा आगणन में रेलवे भाग को सम्मिलित करने हेतु निर्देश दिये गये, जिसके क्रम में विस्तृत आगणन गठित किया गया कार्य के निष्पादन हेतु M/s Ram Kumar Contractor के साथ मुख्य अभ्यन्ता, रा०मा० एवं सेतु (ग०क्षे०) द्वारा अनुबन्ध संख्या ०2CE&B/2016 दिनांक 19/7/2016 लागत ₹ 430000000.00 का अनुबन्ध गठित किया। अनुबन्ध के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 19/7/2016 व समाप्ति की तिथि 18/7/2018) 24 माह थी (

अधशासी अभ्यन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड, लो. नि. व., डोईवाला के अभिलेखों के अनुसार कार्य निष्पादन में आतिथि (अगस्त 2017) तक कुल 26.138% की प्रगति है। ठेकेदार को द्वितीय चल देयक से ₹1246.86 लाख का भुगतान 22 जून (2017) खण्ड द्वारा किया गया था। इस के अतिरिक्त कार्य के निष्पादन में:

- ठेकेदार द्वारा निर्धारित bill of materials के अनुसार work programme खण्ड को उपलब्ध नहीं कराया गया।
- ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध में निर्धारित क्लाइम के अनुसार कार्य का बीमा 4 वर्ष के लिए कराया जाना चाहिये जबकि केवल 2 वर्ष के लिए ही कराया गया है तथा ठेकेदार द्वारा कार्य के बीमा में section II Third Party liability के अन्तर्गत केवल limit of indemnity in respect of any **one accident** or series of accidents arising out of **one event** का कवरेज दिया गया है। जबकि इसे पूर्ण समय के लिये comprehensive (more than one occasion) होना चाहिये
- ठेकेदार से बैंक गारंटी केवल 2 वर्ष की वैधता की प्राप्त की गयी थी जबकि अनुबन्ध के क्लाइम के अनुसार इसकी वैधता 4 वर्ष की होनी चाहिये थी
- अनुबन्ध के अनुसार अब तक (प्रथम 8 माह में 20%, 12 माह में 50%, 18 माह में 70% व 24 माह में 100%) में 50% धनराशि का कार्य पूर्ण किया जाना था परन्तु 13 माह से अधिक का समय होने के पश्चात भी अभी तक केवल 26% कार्य ही किया गया था इसके अतिरिक्त ठेकेदार से कार्य को समयान्तर्गत सम्पादित न कए जाने हेतु खण्ड द्वारा कोई पत्राचार अथवा अर्थदण्ड ठेकेदार के देयक से नहीं काटा गया था

- ठेकेदार को द्वितीय चल देयक तक `1246.86 लाख का भुगतान (22 जून 2017) खण्ड द्वारा किया गया है, जिसमें रॉयल्टी की कटौती नहीं की गयी
- रू0 122.91 लाख का भुगतान भारत सरकार द्वारा **Change of scope** कार्य हेतु भुगतान नियमों (क्लाज 4 ए सर्विस रोड ड्रेन का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त ही भुगतान किया जाय) के विपरीत किया गया, क्योंकि उक्त कार्य पर मात्र 9.18 प्रतिशत ही कार्य किया गया था।

उपरोक्त के सम्बंध में इंगत कए जाने पर खण्ड ने तथ्यों को स्वीकार करते हुये अवगत कराया क एस० बी० डी० के क्लॉजो का अनुपालन व अन्य बिन्दु पर कारवाही सुनिश्चित की जायेगा। खण्ड का उत्तर स्वतः ही लेखा परीक्षा बिन्दु की पुष्टि करता है।

अतः दोनों कार्य पर अनुबन्ध के अनुसार धीमी प्रगति, ठेकेदार के भुगतान देयक से `2.39 लाख की रॉयल्टी कटौती न कया जाना व समय पर ठेकेदार के देयक का भुगतान एस०बी०डी० के क्लॉज 43 के अनुसार नहीं कया जाने व `122.91 लाख का भुगतान भारत सरकार द्वारा **Change of scope** कार्य हेतु भुगतान नियमों के विपरीत किया जाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के सज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 ब

प्रस्तर- 4: वेतन निर्धारण में वसंगति के कारण ₹4.52लाख (केवल मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता, अन्य भत्तो को छोड़कर) का अ धक वेतन भुगतान ।

अ धशासी अ भयन्ता,राष्ट्रीय राजमार्ग खंड, लो. नि. व., डोईवाला के अ भलेखों की जांच में पाया गया हैं श्री मोहन सिंह चौहान , अपर सहायक अ भयंता एवं श्री अर वंद प्रताप सिंह, अपर सहायक अ भयंता की नियु क्त कनिष्ठ सहायक के पद पर2004 मे नियु क्त हुई थी तथा दोनों अ धकारियो की पदोन्नति अपर सहायक अ भयन्ता के पद पर मार्च 2011 को हुई।

उपरोक्त दोनों अ धकारियो की पदोन्नति एक ही वर्ष में अपर सहा.अ भयंता के पद पर हुई थी परन्तु मार्च 2011में अपर सहा.अ भयंता के पद पर पदोन्नति के बाद से वेतन निर्धारण में भन्नता पायी गयी हैं। उक्त अ धकारियो के सेवा पुस्तिका के अवलोकन में पाया गया क पदोन्नति के बाद के वेतन का निर्धारण कस आधार पर व कस शासनादेश के अन्तर्गत कया गया था का उल्लेख नहीं कया गया था।

श्री मोहन सिंह चौहान , अपर सहायक अ भयंताको पदोन्नति पर मूल वेतन क्रमशः ₹18750/=दिया गया जब क श्री अर वंद प्रताप सिंह, अपर सहायक अ भयंता को वेतन आयोग के अनुसार ₹17080/= दिया गया था। इस प्रकार मार्च2011को मूल वेतन ₹17080/= निर्धारित करने पर मार्च 2011से जुलाई 2017 तक श्री मोहन सिंह चौहान , अपर सहायक अ भयंताको कुल ₹4.52 लाख (केवल मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता, अन्य भत्तो को छोड़कर) अ धक वेतन भुगतान कया गया।

उक्त को इ गंत करने पर खण्ड ने उत्तर मे उल्लि खत कया क श्री मोहन सिंह चौहान , अपर सहायक अ भयंता का वेतन निर्धारण अ धशासी अ भयंता, प्रांतीय खंड, लो. नि. व.,उत्तरकाशी द्वारा कया गया हैं। तथा वही से सही वेतन निर्धारण की कार्यवाही की जा रही हैं।

अतः श्री मोहन सिंह चौहान , अपर सहायक अ भयंता,पर₹4.52लाख (केवल मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता, अन्य भत्तो को छोड़कर) की अ धक वेतन दिए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 1: उपखनिजो पर 7.85 लाख की कम रायल्टी वसूला कया जाना।

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-2 संख्या 211/VII-II-13/24-ख/2007 दिनांक 26 फरवरी, 2016, 842/VII-II/2016//24-ख/2007 दिनांक 19 मई 2016 के अधसूचना का स्तम्भ-1 में उल्लिखित उपखनिजों पर रायल्टी दरों को स्तम्भ -2 के अनुसार प्रतिस्थापित/संशोधित किया गया था, तथा यह स्पष्टतः उल्लिखित था कि यह अधसूचना के जारी होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधशासी अभ्यन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड, लो. नि. व., डोईवाला के संबंधित अभिलेखों, माप पुस्तिकाएँ एवं भुगतान वपत्र प्रमाणों की नमूना जाँच में पाया गया कि खण्ड द्वारा संशोधित दरों से रायल्टी की कटौती मार्च 2016, से जुलाई 2017 में नहीं की गयी थी। अधसूचनानुसार खण्डास बोल्डर्स तथा बालू मोरंग या बजरी पर दिनांक- 26.02.2016 से 18 मई 2016 तक 194.50 तथा 19 मई 2016 से अब तक 154.00 प्रति घन मीटर संशोधित/वृद्ध किया गया था। अगर खण्ड द्वारा संशोधित दरों से रायल्टी की कटौती की जाती तो 7.85 लाख रायल्टी के रूप में और राजस्व प्राप्त होती अर्थात् (12.07-4.22 लाख= 7.85 लाख) की राजस्व की कम वसूली हुई है।

उक्त को इंगत करने पर खण्ड ने उत्तर में उल्लिखित किया कि त्रुटिवंश कटौती नहीं हुए हैं। तथा शासनादेश की अनुपलब्धता के कारण ऐसा हुआ यदि वसूली बीजको से संभव नहीं हुए तो जिला अधिकारी के माध्यम से डिपॉजिट में जमा धनराशि से की जायेगी। खण्ड का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अधसूचना में यह स्पष्टतः उल्लिखित था कि यह अधसूचना के जारी होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी तथा सभी कार्यालयों को राज्य सरकार के द्वारा द्रुतगामी उपकरणों जैसे फैक्स, ई-मेल आदि से सुसज्जित किया गया है अतः संशोधित दरों से ही रायल्टी की कटौती की जानी चाहिए थी।

अतः 7.85 लाख रायल्टी की कम वसूली का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

<u>निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या</u>	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	स्टैन
इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा			

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
				-

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु अधशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, डोईवाला तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न लिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:

(i) शून्य

2. सतत अनियमितताएं:

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अवध में निम्न लिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं०	नाम	पदनाम
----------	-----	-------

(i) श्री महिपाल सिंह रावत, अध. अभ. 11/10/2015 से अब तक

(ii) वगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न लिखित खण्डीय लेखाधकारी खण्ड से संबद्ध रहे।

1. श्री एस. एस. चौहान (गठन से 30/07/2016 तक)

2. श्री एस.जी.पाठक (31/07/2016 से अब तक)

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति अधशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, डोईवाला को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार, आर्थिक क्षेत्र-2, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाय।

लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक खण्ड-II